DIVINE
CIVIL SERVICES ACADEMY

RAS

Prelims Practice Book

राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य

- आर्थिक समीक्षा 2022–23
- बजट 2023–24
- प्रमुख नीतियां एवं रिपोर्ट

500+ अभ्यास प्रश्न
(विस्तृत व्याख्या सहित)

राजस्थान प्रैक्टिस सीरीज़ की 4 पुस्तकों की शृंखला की चौथी कड़ी

DIVINE
CIVIL SERVICES ACADEMY

Divine Civil Services Academy के ऐप पर उपलब्ध प्रमुख कोर्सेज़

Rank Improvement Program for RAS Mains

- 500+ घंटो की कक्षाएँ
- प्रसिद्ध अध्यापकों द्वारा अध्यापन
- टॉपिक वाइज़ नोट्स
- 3 वर्ष की वैद्यता अवधि
- मेंटरशिप सपोर्ट

RAS Mains Paper 4th Target 130+ Marks

English : Prof. B. K. Rastogi

Hindi : Sh. Akhilesh Sharma

- 100+ घंटो की कक्षाएँ
- टॉपिक वाइज़ नोट्स
- 3 वर्ष की वैद्यता अवधि

RAS Prelims Test Series 2023

- Strategic Coverage of Complete Syllabus
- High Quality Questions
- Detailed Explanation Sheet for Revision

RAS Mains Test Series 2023

- Strategic Coverage of Complete Syllabus
- High Quality Questions Prepared by our Teachers
- Video Solution by our Expert Faculties
- Scientific Evaluation Methodlogy

Scan QR for our app

For more information Call:

900-900-3843

Publisher :
Divine Civil Services Academy
Main Triveni Chauraha, Gopalpura Bypass,
Jaipur-302018 • Mob.: 900-900-3843
www.divinecivilacademy.com
email: divinecivilacademy@gmail.com

© Publisher

for Trade Order :
College Book Centre
Jaipur-4 (Raj.)
Mob.: 9001072000

RAS प्रारंभिक परीक्षा में राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य से पूछे गये प्रश्नों का ट्रेंड

विषय वस्तु	वर्ष	
	2021	2018
राजस्थान की अर्थव्यवस्था : एक नजर में (तुलनात्मक दृष्टिकोण)	4	3
आर्थिक समीक्षा		
अध्याय-1 वृहद् आर्थिक प्रवृतियों का परिदृश्य	2	1
अध्याय-2 कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	2	1
अध्याय-3 ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज	1	0
अध्याय-4 औद्योगिक विकास	2	3
अध्याय-5 आधारभूत संरचना का विकास	1	1
अध्याय-6 सेवा क्षेत्र	1	1
अध्याय-7 शहरीकरण और शहरी विकास	1	1
अध्याय-8 बुनियादी सामाजिक सेवाएँ – शिक्षा एवं स्वास्थ्य	4	2
अध्याय-9 अन्य सामाजिक सेवाएँ / कार्यक्रम	2	1
अध्याय-10 राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन	1	2
अध्याय-11 सतत् विकास लक्ष्य	1	0
बजट-2023-24	4	3
विभिन्न नीतियाँ एवं रिपोर्ट	3	4
कुल प्रश्न	**29**	**23**

- Without the permission of the publisher, the attempt to reproduce any part of this book by any means or by any technical means (electronic, mechanical, photocopying, recording, digital, web) or the name of this book, titles, illustrations, drawings, maps, designs, cover designs, page layout, settings, literary materials, content may not be published or distributed in any language, either in whole or in part or in the form of distortions or alterations. The copyright of this book is reserved with the publisher.
- The composing work of the book has been done by the computer, in spite of taking full care by the author, proof reader, computer operator and publisher in the writing and publication work of the book, it is possible to have some incomplete or outdated information / some mistakes / shortcomings may remain. For which the printers, authors and publishers associated with the publication of the book will not be responsible. Readers' suggestions are cordially invited.
- The jurisdiction of all disputes will be Jaipur (Raj.).

दो शब्द

राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य से निर्णायक प्रश्न पूछे गए हैं। कोई भी गंभीर अभ्यर्थी इस खंड को यदि अच्छे से तैयार नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे लगभग 20 प्रश्नों का नुकसान उठाना होगा और यह प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों का लगभग 30% अंश है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी आर्थिक समीक्षा और बजट को समझने के लिए आपको आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उन मूलभूत सिद्धांतों और अनुप्रयोगों से परिचित होना आवश्यक है जिनसे अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। सामान्यतः अभ्यर्थी अर्थव्यवस्था को समसामयिकी से जुड़ा विषय ही मानते हैं और केवल आर्थिक समसामयिकी का अध्ययन ही करते हैं, ऐसी स्थिति में विभिन्न मुद्दों पर केवल सतही समझ ही बना पाते हैं। वास्तव में इस खंड से पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ तो समसामयिक होता है, लेकिन इन्हें हल करने के लिए अर्थव्यवस्था की आधारभूत समझ आवश्यक होती है। अतः अभ्यर्थी अर्थशास्त्र की अवधारणाओं को आर्थिक समसामयिकी से जोड़कर अध्ययन करें।

आर्थिक समीक्षा के नाम पर वैसे तो बाज़ार में बहुत-सी पुस्तकें उपलब्ध है और राजस्थान सरकार का प्रामाणिक दस्तावेज भी उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में आपको लग सकता है कि इसमें ऐसा नया क्या है? जो अभ्यर्थी इस पर अपने समय का निवेश करें। आपकी शंका का समाधान करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि यह राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य के वस्तुनिष्ठ अध्ययन का एक स्रोत है जिसे विभिन्न प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर बनाया गया है। इसे प्रारम्भिक परीक्षा के ट्रेंड का सुक्ष्म अध्ययन कर विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से गुजार कर अंतिम रूप दिया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक **'प्रिलिम्स प्रैक्टिस बुक'** की **'राजस्थान प्रैक्टिस सीरीज'** की कुल 4 पुस्तकों की अंतिम कड़ी है। इस पुस्तक में उच्च गुणवत्तायुक्त 500+ विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्न शामिल है। इसमें राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के सभी अध्यायों पर आधारित उन प्रश्नों का संकलन है जिनकी आगामी परीक्षाओं में पूछें जाने की सर्वाधिक संभावना है। इसके अतिरिक्त बजट 2023-24 तथा विभिन्न नीतियों एवं रिपोर्ट पर आधारित प्रश्नों का भी संकलन किया गया है। प्रश्नोत्तर आधारित इस पुस्तक को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाने का लाभ आपको यह होगा कि आप अपनी तैयारी के कमज़ोर और मज़बूत पक्ष को जाँच पाएंगे तथा समय रहते आवश्यक सुधार भी कर पायेंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या से सम्पूर्ण आर्थिक समीक्षा, बजट तथा विभिन्न नीतियों और रिपोर्ट का दोहराव भी आसानी से हो जाएगा।

अब यह पुस्तक राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को समर्पित है। यह पुस्तक प्रस्तुत करते समय हम आपकों भरोसा दिला रहें हैं और दावा भी कर रहे हैं कि राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य की तैयारी के लिए यह पुस्तक निर्णायक सिद्ध होगी।

प्रिलिम्स परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ

संपादक
श्री रामेश्वर सिंह
श्री कमल चौधरी

विषय-क्रम

अध्याय नं. अध्याय का नाम ..... पेज नम्बर

❖ दो शब्द 3

राजस्थान की अर्थव्यवस्था : (एक नज़र में) तुलनात्मक दृष्टिकोण
[Economy of Rajasthan : (At a Glance) Comparative Perspective] 5

1 वृहद् आर्थिक प्रवृतियों का परिदृश्य
[Overview of Macro Economic Trends] 11

2 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र
[Agriculture & Allied Sectors] 21

3 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
[Rural Development & Panchayati Raj] 33

4 औद्योगिक विकास
[Industrial Development] 39

5 आधारभूत संरचना का विकास
[Infrastructure Development] 50

6 सेवा क्षेत्र
[Service Sector] 57

7 शहरीकरण और शहरी विकास
[Urbanization and Urban Development] 66

8 बुनियादी सामाजिक सेवाएं : शिक्षा एवं स्वास्थ्य
[Basic Social Services: Education and Health] 73

9 अन्य सामाजिक सेवाएँ एवं कार्यक्रम
[Other Social Services and Programs] 81

10 राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन
[State Finance and Other Resources of Development] 88

11 सतत् विकास लक्ष्य
[Sustainable Development Goals] 96

12 बजट : 2023-24
[Budget : 2023-24] 101

13 विभिन्न नीतियाँ एवं रिपोर्ट
[Various Policies and Reports] 110

❐❐❐

1. किसी भी राज्य के आर्थिक विकास को मापते समय निम्नलिखित में से किन मापदंडों पर विचार किया जाता है—

1. वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
2. जीवन की गुणवत्ता और प्रत्याशा
3. वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद
4. गरीबी सूचकांक
5. लिंग संबंधी विकास सूचकांक।

उपर्युक्त में से कौनसा/से विकल्प सही है/हैं?

(A) केवल 1, 2, 3 और 5 (B) केवल 1, 2, 3 और 4
(C) केवल 1, 2 और 3 (D) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर–(D)

व्याख्या—राज्य की समृद्धि को मापने के लिए राज्य के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को भी मापा जाता है। आर्थिक विकास सकल घरेलू उत्पाद के साथ-साथ बाजार उत्पादकता में वृद्धि का परिणाम है। ऐसे कई मापदंड है जिन पर आर्थिक विकास को मापते समय विचार करने की आवश्यकता है, जो इस प्रकार है—

2. स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
2. स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की जीएसडीपी पिछले पाँच वर्षों से लगातार बढ़ रही है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर–(A)

व्याख्या—स्थिर (2011-12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

- राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है।
- स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की वास्तविक जीएसडीपी में पिछले तीन वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है।

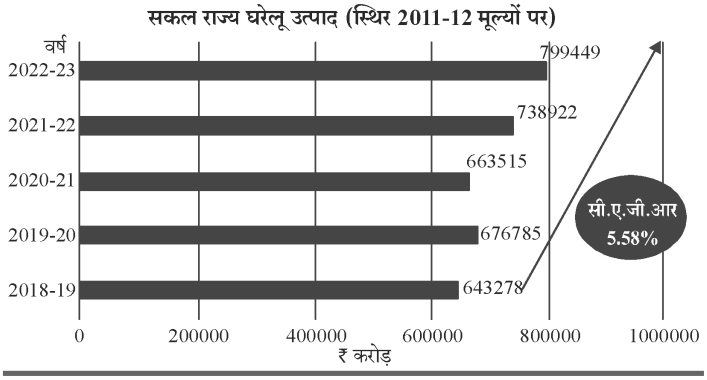

3. प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

1. प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी अनुमान, समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट करता है।
2. वर्ष 2022-23 में प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी में पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन असत्य है/हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर–(A)

व्याख्या—प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

- प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ज्ञात करने के लिए एक वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।
- प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है क्योंकि इसमें निम्न का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित है—
  (i) वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन
  (ii) वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन
- अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022-23 में ₹14.4 लाख करोड़ संभावित है, जो कि वर्ष 2021-22 में ₹12.18 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2021-22 के 19.50 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022-23 में 16.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

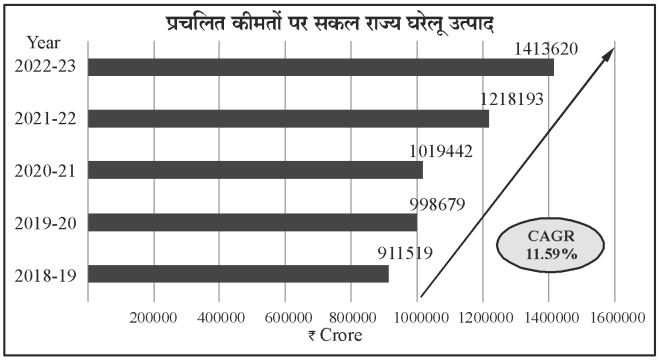

4. वर्ष 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर अखिल भारतीय अनुमानित जीडीपी है—

(A) राजस्थान की अनुमानित जीडीपी से पांच गुना अधिक।

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. राज्य की जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है।
2. राजस्थान में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर- (B)

व्याख्या—

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हैं।	• राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। राज्य में मानसून की अवधि कम तथा राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में विलम्ब से आता है एवं जल्दी ही वापसी हो जाती है। वर्षा की अवधि में भी उतार–चढ़ाव रहता है, जो अपर्याप्त कम एवं अनिश्चित रहती है।
इसके अतिरिक्त राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है।	
जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहती है।	• इसके बावजूद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है एवं जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) में इसका प्रमुख योगदान है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:-

1. आर्थिक समीक्षा-2022-23 के अनुसार राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2011-12 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56 प्रतिशत था जो 2022-23 में बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया।
2. वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में फसल क्षेत्र का योगदान सबसे कम 7.20% प्रतिशत अनुमानित किया गया है।
3. वर्ष 2022-23 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में मत्स्य क्षेत्र का योगदान लगभग 0.39 प्रतिशत था।

उपर्युक्त में से कौन सा/से असत्य कथन है?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) 1, 2 और 3

उत्तर- (A)

व्याख्या—

- राजस्थान के जी.एस.वी.ए. में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान और इसके उप क्षेत्रों की संरचना:-
  - ✧ राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2011-12 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56 प्रतिशत था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 28.95 प्रतिशत हो गया।
  - ✧ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उप क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य तथा वानिकी एवं लॉगिंग हैं।
  - ✧ 2022-23 में फसल क्षेत्र का अंश 46.00 प्रतिशत, पशुधन क्षेत्र का अंश 46.41 प्रतिशत, वानिकी क्षेत्र का अंश 7.20 प्रतिशत और मत्स्य क्षेत्र का अंश 0.39 प्रतिशत है।
- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में योगदान :

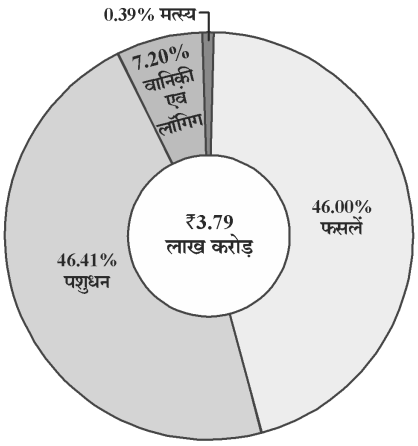

3. वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना रहा है?

(A) 5 लाख करोड़ (B) 7.2 लाख करोड़
(C) 1.76 लाख करोड़ (D) 2.76 लाख करोड़

उत्तर-(C)

व्याख्या—वर्ष 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 1.76 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अंडे और मांस का प्रमुख योगदान है।

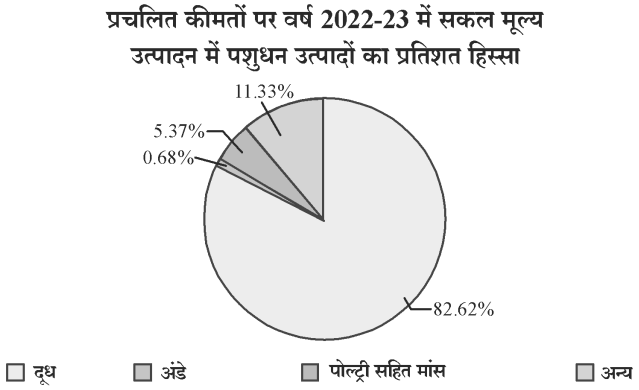

4. भू-उपयोग सांख्यिकी 2020-21 के अनुसार, भू–उपयोग में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक प्रतिशत योगदान रहा है?

(A) वानिकी
(B) शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल
(C) स्थायी चारागाह
(D) कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि।

उत्तर-(B)

व्याख्या—भू–उपयोगी—राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2020-21 में 342.89 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 8.08 प्रतिशत क्षेत्रफल (27.72 लाख हैक्टेयर) वानिकी के अंतर्गत, 5.86 प्रतिशत क्षेत्रफल (20.10 लाख हैक्टेयर) कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि के अंतर्गत, 6.91 प्रतिशत क्षेत्रफल (23.67 लाख हैक्टेयर) ऊसर तथा

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम/योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
2. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इन योजनाओं का मूल उद्देश्य गरीबी को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना इत्यादि हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) न तो 1 और न ही 2 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—(D)

व्याख्या—ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के उद्देश्य–

1. गरीबों को कम करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना।
3. मजदूरी आधारित रोजगार व स्वरोजगार में वृद्धि करना।
4. विकास व ग्रामीण आवास में क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना।

2. ''राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्'' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. इसकी (राजीविका) स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में जनवरी 2005 में एक स्वायत्त परिषद् के रूप में की गई।
2. यह परिषद् सोसायटी पंजीकरण अधिनियिम, 1965 के अंतर्गत पंजीकृत है।
3. इसे स्वयं सहायता समूह आधारित सांस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन **असत्य** है?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(A)

व्याख्या— राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (R.G.A.V.P.)–

- राजीविका (R.G.A.V.P.) की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर, 2010 में एक स्वायत्त परिषद् के रूप में की गई।
- यह परिषद् सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है।
- राजीविका को स्वयं सहायता समूह आधारित सांस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने कार्य सौंपा गया है।

3. निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए–

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)
2. प्रधानमंत्री-आवास योजना।
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।

उपर्युक्त में से कौनसी ऐसी आजीविका योजना/योजनाएं है जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और राजीविका (राज. ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है/हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 1 और 2 (D) केवल 2 और 3

उत्तर—(A)

व्याख्या—1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन–(एन.आर.एल.एम.)

- यह मिशन सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल उपलब्ध राशि ₹412.30 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध ₹341.41 करोड़ व्यय किये गये तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नवम्बर 2022 तक ₹412.40 करोड़ बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹209.34 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना– यह परियोजना राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों में संचालित की जा रही है।

4. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए–

योजना	**कार्यान्वयन विभाग**
a. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1. ग्रामीण विकास मंत्रालय
b. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2. गृह मंत्रालय
c. प्रधानमंत्री आवास योजना	3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

कूट :–

	a	b	c
(A)	1	3	2
(B)	3	2	1
(C)	1	2	3
(D)	2	3	1

उत्तर—(B)

व्याख्या— इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबी को कम करना, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, मजदूरी आधारित रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और विकास व ग्रामीण आवास में क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना है।

• निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा इस प्रकार क्रियान्वित किये जा रहे हैं–

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा–

- आजीविका परियोजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- पीएम आवास योजना
- सांसद आदर्श ग्राम योजना

2. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय–

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

3. राजस्थान सरकार द्वारा–

- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
- मेवात विकास कार्यक्रम
- महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना
- स्व-विवेक जिला विकास योजना (2005-06)
- डांग-क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- मगरा-क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

4. गृह मंत्रालय द्वारा–

- सीमा-क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1. निम्न कथनों पर विचार कीजिए–

(1) बजट भाषण 2022-23 के अनुपालन में आगामी वर्षों में **कुल 2245 मेगावाट** क्षमता की नई **कोयला** आधारित ताप विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

(2) इसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित छबड़ा विद्युत परियोजना की इकाइयों का विस्तार किया जायेगा।

उपरोक्त कथनों में से कौनसा/से कथन सत्य हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2

(C) न तो 1 और न ही 2 (D) 1 और 2 दोनों

उत्तर—(D)

व्याख्या–

✧ बजट भाषण 2022-23 के अनुपालन में आगामी वर्षों में कुल 2245 मेगावाट क्षमता की नई कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित छबड़ा विद्युत परियोजना, इकाई-7 एवं इकाई-8 का विस्तार छबड़ा में 660-660 मेगावाट और काली सिंध में 800 मेगावाट की 3-यूनिट शामिल है।

✧ इससे रोजगार और विकास के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, साथ ही राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

(1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पुगल (बीकानेर) में 818 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र सहित कुल 3000 मेगावाट सौर पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गई है।

(2) राजस्थान के खनिज संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार के नये आयाम स्थापित करने के लिए बीकानेर के गुरहा में 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना ''इकाई-1'' की स्थापना प्रक्रिया जारी है।

(3) ऊर्जा को प्राय ''अर्थव्यवस्था की रीढ़'' कहा जाता है। यह क्षेत्र सभी क्षेत्रों (कृषि, सेवा उद्योग) की आर्थिक गतिविधियों को चहुमुखी विकास के आयाम प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सत्य हैं?

(A) केवल 1 और 3 (B) केवल 2 और 3

(C) केवल 1 और 2 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—(B)

व्याख्या–

✧ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पुगल (जिला बीकानेर) में 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र सहित कुल 2000 मेगावाट सौर पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गई है।

✧ परियोजना के लिए भूमि का आवंटन पूरा हो चुका है और इस स्वीकृति के साथ आर.वी.यू.एन.एल. ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाएं हैं साथ ही राजस्थान की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया है।

3. वर्षवार ऊर्जा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता के संदर्भ में असुमेलित की पहचान कीजिए–

ऊर्जा विवरण		ऊर्जा क्षमता (मेगावाट) वर्ष 2022-23
(A) तापीय ऊर्जा	–	7830 MW
(B) जल विद्युत ऊर्जा	–	1117.29 MW
(C) सौर ऊर्जा	–	3348.60 MW
(D) पवन ऊर्जा	–	3730.35 MW

उत्तर—(B)

व्याख्या–

वर्षवार ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता

(मेगावाट)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1. राज्य की स्वंय/भागीदारी की परियोजनाएँ						
(अ)	तापीय	5850.00	6510.00	7170.00	7830.00	7830.00
(ब)	जल विद्युत	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29
(स)	गैस	603.50	603.50	603.50	603.50	603.50
2. केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित						
(अ)	तापीय	1793.50	1870.46	1903.46	1947.41	1916.37
(ब)	जल विद्युत	740.66	740.66	740.66	740.66	740.66
(स)	गैस	221.10	221.10	221.10	221.10	221.10
(द)	तापीय/जल विद्युत	456.74	456.74	456.74	456.74	456.74
3. आरआरइसी, आरएसएमएमएल एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/बायोमास/सौर ऊर्जा परियोजनाएं						
(अ)	पवन	4139.20	3734.10	3734.10	3734.10	3730.35
(ब)	बायोमास	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95
(स)	सौर ऊर्जा	2411.70	2178.10	2288.10	3057.60	3348.60
(द)	तापीय/जल विद्युत	3742.00	3742.00	3742.00	3742.00	3742.00
योग (3)		**10394.85**	**9756.15**	**9866.15**	**10635.65**	**10922.90**
सकल योग (1+2+3)		**21077.64**	**21175.90**	**21978.90**	**23452.35**	**23487.46**

*नवम्बर, 2022 तक

**22 मार्च, 2021 को जारी विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देश के मद्देनजर उच्च खरीद लागत के कारण एनटीपीसी से 221 मेगावाट गैस बिजली का आवंटन वापस कर दिया गया था।

4. निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए–

(A) राजस्थान में मार्च 2019 तक कुल E.H.V. (ई.एच.वी) प्रसारण नेटवर्क 41104.39 सर्किट कि.मी. था, जो मार्च 2022 तक बढ़कर 43484.743 सर्किट कि.मी. हो गया है।

(B) प्रसारण तंत्र प्रणाली में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 की अवधि में कुल प्रसारण नेटवर्क में 4.8% की वृद्धि हुई है।

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

(1) सेवा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ जिनमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और दूर संचार जैसी उच्च दक्षता वाली गतिविधियों से लेकर प्लम्बर द्वारा दी जाने वाली साधारण सेवा तक की विभिन्न गतिविधियाँ सम्मिलित हैं।

(2) राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल, वित्तीय बीमा, स्थावर संपदा, व्यावसायिक सेवाएं, तथा सामाजिक, सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित है।

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन असत्य हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2

(C) न तो 1 और न ही 2 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(C)

व्याख्या—सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियाँ जिनमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और दूर संचार जैसी उच्च दक्षता वाली गतिविधियों से लेकर प्लम्बर द्वारा दी जाने वाली साधारण सेवा तक की विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है।

- राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल और जलपानग्रह, परिवहन, भण्डार एवं संचार, वित्तीय बीमा, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित हैं।

2. सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर उप–क्षेत्रवार योगदान वितरण (प्रतिशत में) 2022–23 के सन्दर्भ में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए:

उप – क्षेत्र	वितरण प्रतिशत (योगदान)
(A) लोक प्रशासन	7.07
(B) वित्तीय सेवाएँ	41.18 %
(C) परिवहन, भण्डार, संचार	11.78
(D) अन्य सेवाएं	19.57%

उत्तर—(B)

व्याख्या—सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप–क्षेत्रवार वितरण 2022-23

क्र.सं.	उप – क्षेत्र	वितरण (प्रतिशत में)
1.	लोक प्रशासन	7.07 %
2.	स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं	24.62%
3.	वित्तीय सेवाएं	9.27%
4.	परिवहन, भण्डार, संचार	11.78%
5.	व्यापार होटल तथा जलपान गृह	27.69%
4.	अन्य सेवाएं	19.57%

3. सेवा क्षेत्र के स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2022–23 में कितने लाख करोड़ अनुमानित हैं ?

(A) रू 13 लाख करोड़ (B) रू 3.21 लाख करोड़

(C) रू 4.21 लाख करोड़ (D) रू 7.31 लाख करोड़

उत्तर—(B)

व्याख्या—सेवा क्षेत्र के स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी. एस. वी. ए.) वर्ष 2018–19 में रू 2.78 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2022–23 में रू 3.21 लाख करोड़ अनुमानित है। यह इस अवधि में प्रतिवर्ष 3.65% (सी. ए. जी. आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता हैं।

4. राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022–23 में सेवा क्षेत्र का प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर योगदान प्रतिशत हैं–

(A) 45.56 % (B) 43.74%

(C) 48.55% (D) 74.81%

उत्तर—(B)

व्याख्या—राजस्थान की अर्थव्यस्था में 2022–23 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित बुनियादी मूल्य पर 43.74 प्रतिशत योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है।

वर्ष 2022–23 में सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप–क्षेत्रवार वितरण चित्र में दर्शाया गया है–

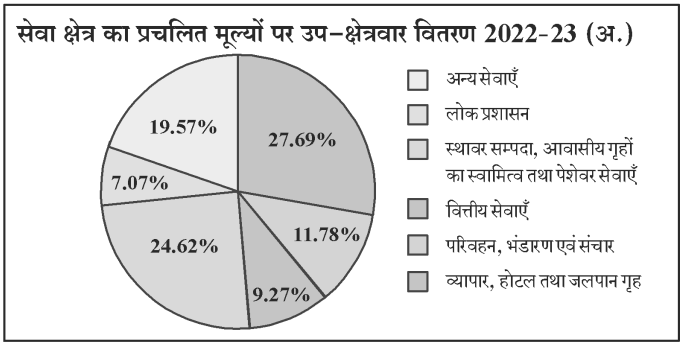

5. कथन (A) राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022–23 में सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान 17.07% रहा हैं।

कारण (R) लोक प्रशासन सेवाओं के अतिरिक्त जैसे–व्यापार, होटल, जलपान ग्रह आदि का भी राजस्थान के सेवा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा हैं।

कूट–

(A) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण हैं।

(B) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, परंतु कारण (R), कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(C) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों गलत हैं।

(D) कथन (A) गलत परंतु कारण (R) सही हैं।

उत्तर—(D)

व्याख्या—राजस्थान राज्य के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान

1. संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास रिपोर्ट 2022 के निष्कर्षों के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए–

1. इसके अनुसार विश्व की लगभग 70% से अधिक आबादी शहरों में रहती है।
2. शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80% योगदान है।
3. शहरीकरण आर्थिक विकास का इंजन है।

उपर्युक्त में से कौन–सा/से कथन सत्य हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(B)

व्याख्या—संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास रिपोर्ट, 2022 के अनुसार विश्व की आधी आबादी शहरों में निवास कर रही है और इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 70% तक होने का अनुमान है। शहरीकरण विकास का इंजन है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि शहरों और महानगरों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 80% योगदान है।

2. राजस्थान में शहरीकरण की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नांकित में से कौनसा विकल्प असत्य है?

(A) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या प्रतिशत भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत की तुलना में कम है।
(B) वर्ष 2031 की जनगणना के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में शहरी जनसंख्या 34.43% हो जायेगी।
(C) वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या 24.87% है।
(D) 1961 से राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत हिस्सेदारी अनवरत बढ़ी है।

उत्तर—(B)

व्याख्या—शहरीकरण की प्रवृत्ति राजस्थान में भी राष्ट्रीय स्तर के समान ही बढ़ रही है। भारत की कुल जनंसख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 2011 में 31.14% हो गयी और राजस्थान में 24.87%। राजस्थान की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत में वर्ष 2021 में 26.33% तथा वर्ष 2031 में 27.74% वृद्धि अनुमानित है। राजस्थान की शहरी जनसंख्या में 1961 से लगातार हिस्सेदारी बढ़ी है।

3. 'राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग' के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए–

1. इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
2. यह 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' के अंतर्गत कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कौन–सा/से कथन असत्य हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—(D)

व्याख्या—राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, भारत सरकार का एक आयोग है। इसका गठन 11 मई 2000 को किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वर्तमान में यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है।

4. बाल–लिंगानुपात के संबंध में निम्नांकित विकल्पों में से कौनसा/से विकल्प असत्य है?

(A) बाल–लिंगानुपात में 0-6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता हैं।
(B) 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी बाल–लिंगानुपात 2001 की जनगणना की तुलना में कम हुआ हैं।
(C) राजस्थान में 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या में वर्ष 2001 से 2011 के बीच तेजी से वृद्धि हुई है।
(D) विकल्प B और C दोनों।

उत्तर—(C)

व्याख्या—राजस्थान में 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 व 2011 के बीच लगभग समान रही है। वर्ष 2011 में बच्चों की कुल शहरी जनसंख्या में 53.37% लड़के व 46.63% लड़कियाँ थीं, जबकि 2001 में 52.98% लड़के व 47.02% लड़कियाँ थीं, जो बाल लिंगानुपात में गिरावट को दर्शाता है। बाल लिंगानुपात में 0-6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है।

5. लिंगानुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य राजस्थान है।
2. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914/1000 तथा ग्रामीण लिंगानुपात 933/1000 था।
3. वर्ष 2001 से 2011 के बीच शहरी लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात की तुलना में अधिक बढ़ा है।

उपर्युक्त में से कौन–सा/से कथन सत्य हैं?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(B)

व्याख्या—वर्ष 2011 में राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरूषों पर 914 महिलाओं का था, जो वर्ष 2001 में प्रति हजार पुरूषों पर 890 महिलाएं थी। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक संतुलन रहा है। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरूषों पर 933 महिलाओं का है, जो शहरी क्षेत्र की तुलना में थोड़ा अधिक है। वर्ष 2001 में, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरूषों पर 930 महिलाओं का था। यह स्पष्ट करता है कि 2001 से 2011 के बीच शहरी लिंगानुपात में ज्यादा वृद्धि हुई है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा (877) है।

6. बाल–लिंगानुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए–

1. राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र ने शहरी क्षेत्र की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
2. वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बाल-लिंगानुपात में गिरावट देखी गई है।

उपर्युक्त में से कौन–सा/से कथन असत्य हैं?

1. 'नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना' के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए –

1. इसके अंतर्गत राज्य सरकार, राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से पुस्तकें उपलब्ध करवाती हैं।
2. इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी विधार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें व अन्य पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन असत्य हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर–(B)

व्याख्या—नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना– इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा–1 से 8 तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवा रही हैं।

2. 'विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना' के संदर्भ में निम्नाकिंत कथनो पर विचार कीजिए–

1. यह योजना राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है।
2. वित्तीय वर्ष 2022–23 में इसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया है।
3. इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों व मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों को शामिल नहीं किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन–सा/से कथन सत्य हैं ?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर–(B)

व्याख्या—विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना– यह योजना राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के कक्षा–1 से 8 तक के विद्यार्थियों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों एवं वैकल्पिक शिक्षा के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त योजना को राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है।

3. ''मुख्यमंत्री संबल योजना' के संदर्भ में निम्नाकिंत कथनों पर विचार कीजिए–

1. यह योजना विधवा/परित्यकता महिलाओं के लिए है।
2. इसमें ऐसी महिलाओं को निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारंम्भिक शिक्षा में 3 वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन का अध्ययन करने पर ₹9000 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन सत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 और 2 दोनों (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर–(A)

व्याख्या—विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्बल योजना– इस योजना के अन्तर्गत निजी प्रशिक्षण सस्थानों में प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन (डी.एल.ई.डी.) का अध्ययन करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को रू 9,000 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है।

4. 'बाल वाटिका योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए–

कथन (S) : बालवाटिका योजना का राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में प्रावधान किया गया है।

कारण (R) : इसके अंतर्गत 4 से 6 वर्ष की आयु तक के पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों को एक वर्ष तक अध्ययन करवाया जायेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से सही है?

(A) कथन (S) और कारण (R) दोनों सही है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(B) कथन (S) और कारण (R) दोनों सही है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(C) कथन (S) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (S) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

उत्तर–(B)

व्याख्या—बाल वाटिका योजना–राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में राजकीय विद्यालयों में बालवाटिका एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं प्रारम्भ किये जाने के संबंध में प्रावधान किये गये है। प्रारंम्भिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान की नींव को मजबूत करने के लिये बालवाटिका का संचालन एक सकारात्मक पहल है। बालवाटिका योजना के अन्तर्गत 04 से 06 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे है, उन्हें एक वर्षीय बालवाटिका मे अध्ययन करवाकर कक्षा–1 हेतु तैयार करने के लिये चरणबद्ध प्रयास किये जाने प्रस्तावित हैं।

5. निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए–

1. भामाशाह सम्मान समारोह योजना की शुरूआत 1 जनवरी 1995 से की गई थी।
2. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगाठ पर ''आजादी अमृत महोत्सव'' मनाया गया।
3. स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत केवल राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्धियों का स्वास्थ्य परिक्षण किया जाता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है ?

(A) केवल एक (B) केवल दो
(C) सभी तीनों (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर–(B)

व्याख्या—भामाशाह सम्मान समारोह–यह योजना 1 जनवरी, 1995 से विद्यालय के शैक्षिक, सह–शैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से दानदाताओं को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम–एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगाठ पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया गया।

स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। राज्य में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा किशोरी आयु की बालिकाओं (10–19 आयु वर्ग) के लिए एनिमिया नियंत्रण का एक अलग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

1. जलजीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

(1) इसकी शुरूआत 15 अगस्त 2019 से की गई।
(2) वर्ष 2025 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है।
(3) इस योजना में केन्द्र व राज्य की भागीदारी 75:25 प्रतिशत है।

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से कथन सत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—(A)

व्याख्या—जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन की शुरूआत 15 अगस्त 2019 से की गई। यह योजना केन्द्र व राज्य की 50:50 प्रतिशत भागीदारी से संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल की आपूर्ति करवाना है। इसके अंतर्गत 10,655 एकल जलप्रदाय योजनाएं एवं 133 वृहद् पेयजल परियोजनाएं शामिल है। इस योजना के तहत दिसम्बर 2022 तक 32.06 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर 11407.25 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

2. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ढाणियों में आर.ओ. प्लांट्स लगाने का कार्य किस विभाग द्वारा किया जाता है?

(A) सार्वजनिक निर्माण विभाग
(B) जन स्वास्थ्य आभियांत्रिकी विभाग
(C) चिकित्सा विभाग
(D) शिक्षा विभाग

उत्तर—(B)

व्याख्या—जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ढाणियों में आर.ओ. प्लांट्स लगाने का कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पेयजल के खारेपन एवं फ्लोराइड की समस्याओं सहित बहु-गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं का समाधान आर.ओ. प्लांट्स स्थापित कर किया जाता है। अब तक 4105 आर.ओ. प्लांट्स स्वीकृत कर 3992 प्लांट्स नवम्बर 2022 तक चालू किये जा चुके है।

3. सौर ऊर्जा आधारित बोरवेल पम्पिंग सिस्टम के तहत नवम्बर 2022 तक कुल कितने संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं?

(A) 2594 (B) 2408
(C) 2508 (D) 2301

उत्तर—(B)

व्याख्या—राज्य में पानी की कमी और अनियमित विद्युत आपूर्ति वाले दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित 2594 बोरवेल पम्पिंग प्रणाली प्रारंभ करने के लिए परियोजना आरम्भ की गई। नवम्बर 2022 तक कुल 2408 संयंत्र स्थापित किये जा चुके है।

4. ''मिड-डे मील योजना'' के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए—

(1) इस योजना का उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाना है।
(2) इसके तहत कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पोषण प्रदान किया जाता है।
(3) यह योजना 66,000 सरकारी विद्यालयों एवं संस्थानों में लागू है।
(4) इसके तहत कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए भोजन में क्रमश: न्यूनतम 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन तथा 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौनसा/से कथन असत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3 (D) उपरोक्त सभी

उत्तर—(C)

व्याख्या—मिड-डे मील योजना का मूल उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों और मदरसों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार लाना है। यह कार्यक्रम 67,327 सरकारी विद्यालयों एवं संस्थानों में लागू है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ने वाले लगभग 69.22 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी क्रमश: 100 ग्राम और 150 ग्राम (गेहूं/चावल) प्रतिदिन प्रदान किये जाते है। इसके तहत वितरित किये जाने वाले भोजन में कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए क्रमश: 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन और 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होता है।

5. 'मुख्यमंत्री बाल गोपाल' योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए—

(1) इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह के तीन दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाता है।
(2) इसके तहत Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited द्वारा मिल्क पाउडर 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से विद्यार्थियों में आपूर्ति की जा रही है।
(3) इस योजना के अंतर्गत दूध के लिए नवीन विद्यालयों को बर्तन क्रय हेतु अधिकतम 15,000 रुपये प्रति विद्यार्थी गिलास क्रय हेतु 40 रुपये की दर से अतिरिक्त आवंटित किया जा रहा है साथ ही दूध गर्म करने हेतु 1500 रुपये प्रतिमाह गैस सिलैण्डर हेतु दिए जाते है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3 (D) केवल 3

उत्तर—(A)

व्याख्या—मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना- मिड-डे मील योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यार्थियों को इस योजना में सप्ताह में दो दिवस (मंगलवार, शुक्रवार) मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाता है।

- इसमें 1 किलोग्राम की पैकिंग के मिल्क पाउडर का Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited द्वारा 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करवाया जाता है।
- प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 150 मिलीमीटर दूध जिसमें चीनी की

1. वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा कितना रहा है?

(A) रू 25,870 करोड़ (B) रू 26,000 करोड़

(C) रू 27,000 करोड़ (D) रू 18,000 करोड़

उत्तर—(A)

व्याख्या—राजस्व घाटा-वर्ष 2021-22 में रू 25870 करोड़ रहा। यह उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान के स्थान पर राशि रू 7,268 करोड़ का ऋण स्वीकृत करने के घटक को समायोजित करने पर राजस्व घाटा रू 18602 करोड़ रहा है।

2. वर्ष 2021-22 के राजकोषीय घाटे के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संशोधित अनुमानों पर वास्तविक राजकोषीय घाटा रू 48,238 करोड़ रहा है।
2. यह राज्य सकल घरेलु उत्पाद का 3.96 प्रतिशत है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2

(C) केवल 1 और 2 (D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर—(C)

व्याख्या—राजकोषीय घाटा-वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमानों में अनुमानित रू 62,015 करोड़ के स्थान पर वास्तविक राजकोषीय घाटा रू 48,238 करोड़ रहा, जो कि राज्य सकल घरेलु उत्पाद का 3.96 प्रतिशत है। संशोधित अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 5.18 प्रतिशत अनुमानित किया गया था।

3. राजस्व व्यय के सेवा वार व्यय में किन सेवाओं का व्यय सर्वाधिक है?

(A) सामान्य सेवाएं (B) सामाजिक सेवाएं

(C) आर्थिक सेवाएं (D) अन्य सेवाएं

उत्तर—(B)

व्याख्या—वर्ष 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व व्यय रू 209790 करोड़ हैं जिसमें सामान्य सेवाओं का व्यय रू 65406 (31.16%), सामाजिक सेवाओं का रू 85054 (40.54%) और आर्थिक सेवाओं का रू 59330 (28.28%) करोड़ है।

4. व्यय की प्रवृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2021-22 में 78.41 % रहा है।
2. वर्ष 2021-22 में वेतन तथा मजदूरी पर व्यय, कुल व्यय (पेंशन भुगतान और ब्याज को छोड़कर) का 39 प्रतिशत रहा है।
3. वर्ष 2021-22 में विकासात्मक व्यय अर्थात सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय रू 168673 करोड़ का रहा, जो कि समग्र व्यय का 71.9 प्रतिशत हैं ?

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2

(C) केवल 1 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर-(B)

व्याख्या—व्यय की प्रवृत्ति-राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2021-22 में 69.21 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021-22 में 78.41 प्रतिशत रहा है तथा शेष राशि पूंजीगत प्राप्तियों एवं ऋण से पूरित की गई है। वर्ष 2021-22 में योजनाओं पर व्यय राशि रू 138261 करोड़ हुआ जो कि गत वर्ष की तुलना में 35.85 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2021-22 में वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, कुल व्यय (पेंशन भुगतान व ब्याज को छोड़कर) का 36.08 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2021-22 में वेतन तथा मजदूरी में पिछले वर्ष की तुलना में 10.65 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2021-22 में विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय रू 168673 करोड़ रहा, जो कि समग्र व्यय का 71.9 प्रतिशत है।

5. राजकोषीय देनदारियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ष 2021-22 में राजकोषीय देनदारियाँ रू 4,62845 करोड़ रही।
2. वर्ष 2020-21 की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 12.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
3. राजकोषीय देनदारियाँ अतिरिक्त ऋण (जी. एस.टी. क्षतिपूर्ति तथा पूंजीगत व्यय हेतु) को कम करने के पश्चात रू 433,279 करोड़ रही, जो कि राज्य सकल घरेलु उत्पाद का 41 प्रतिशत है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2

(C) केवल 1 और 2 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(C)

व्याख्या—राजकोषीय देनदारियाँ (ऋण एवं अन्य दायित्व)-वर्ष 2020-21 के अन्त मे कुल राजकोषीय देनदारियाँ रू 4,10,499 करोड़ थी, जिसमें रू, 346 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2022 को यह रू 462845 करोड़ हो गई। इस प्रकार वर्ष 2020-21 की तुलना में राजकोषीय देनदारियों में 12.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजकोषीय देनदारियाँ अतिरिक्त ऋण (जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति तथा पूंजीगत व्यय हेतु) को कम करने के पश्चात् राशि रू 449279 करोड़ रही जो कि राज्य सकल घरेलु उत्पाद का 36.88 प्रतिशत है। राजकोषीय देनदारियों के घटक इस प्रकार है -

(i) आन्तरिक ऋण रू 321807 करोड़

(ii) केन्द्र सरकार से ऋण रू 31749 करोड़

(iii) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि रू 58,786 करोड़

(iv) आरक्षित निधि एवं जमा रू 50,503 करोड़

6. राजकोषीय समेकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(1) वर्ष 2021-22 में राजकोषीय देनदारियों का राजस्व प्राप्तियों में अनुपात 270 प्रतिशत रहा।

11 सतत् विकास लक्ष्य [Sustainable Development Goals]

1. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने किस सत्र के दौरान 25 सितम्बर 2015 को ''ट्रांसफार्मिंग अवर वर्ल्ड : द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट'' शीर्षक वाले दस्तावेज को अपनाया है ?

(A) 71 वें सत्र (B) 70 वें सत्र

(C) 79 वें सत्र (D) 72 वें सत्र

उत्तर—(B)

व्याख्या— संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें सत्र के दौरान 25 सितम्बर 2015, को 'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट' शीर्षक वाले दस्तावेज को अपनाया, जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य एवं 169 संबद्ध टार्गेट्स सम्मिलित थे।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

(1) एस.डी.जी. सभी के लिए एक बेहतर एवं सतत् भविष्य को प्राप्त करने का ब्लू-प्रिंट है।

(2) सतत् विकास लक्ष्य, एजेण्डा - 2030 के केन्द्र में 5 महत्त्वपूर्ण आयाम- लोग (People), समृद्धि (Prosperity), ग्रह (Planet), भागीदारी (Partnership), एवं शांति (Peace) है, जिन्हे 5 पीज् (5Ps) के नाम से जाना जाता है।

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन असत्य हैं?

(A) केवल 1 (B) केवल 2

(C) न तो 1 और न ही 2 (D) उपर्युक्त सभी।

उत्तर—(C)

व्याख्या—सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

- सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) सभी के लिए एक बेहतर एवं सतत् भविष्य को प्राप्त करने का ब्लू-प्रिंट है।
- एस.डी.जी. 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए हैं।
- एस.डी.जी. विकास के तीन आयामों को एकीकृत करने वाले वैश्विक लक्ष्यों की एक व्यापक सूची है। इसके अलावा, एस.डी.जी. सार्वभौमिक (सभी विकसित, विकासशील व कम विकसित देशों के लिये), अन्त:सबंधित एवं अविभाज्य है इसलिए सभी को एक साथ लाने के लिए व्यापक एवं भागीदारी वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि 'कोई भी पीछे ना रहे।' प्रत्येक लक्ष्य के टार्गेट्स को संकेतकों के साथ संबद्ध किया गया है, जो मापने योग्य परिणामों पर केन्द्रित/आधारित है।

3. ''एस.डी.जी. इण्डिया इन्डेक्स'' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए –

(1) नीति आयोग द्वारा S.D.G. इण्डिया इण्डेक्स एवं बोर्ड डिजाइन विकसित किया गया है, जो S.D.G. मॉनिटरिंग हेतु किये गऐ प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

(2) एस.डी.जी. इंडेक्स का उद्देश्य अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, राज्यों/केन्द्रीय प्रदेशों के सांख्यिकी तंत्रो के डेटा गेप्स को रेखांकित करने तथा उन क्षेत्रों की पहचान करने, जिनमें सुदृढ़ एवं निरंतर अधिक डाटा संग्रहण की आवश्यकता हैं, में राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों का सहयोग करना है।

(3) S.D.G. इण्डिया इन्डेक्स का प्रथम संस्करण दिसम्बर 2019 में जारी किया गया।

उपर्युक्त में से कौनसा/से कथन असत्य है ?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2

(C) केवल 3 (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तर—(C)

व्याख्या—

- नीति आयोग द्वारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स एवं डेशबोर्ड डिजाइन एवं विकसित किया गया है, जो एस.डी.जी. मॉनिटरिंग हेतु किये गये प्रयासो में से एक महत्त्वपूर्ण साधन है।
- यह इंडेक्स, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गोल्स एवं टार्गेट्स में की गई प्रगति को मापता है।
- इडेंक्स का उद्देश्य अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सांख्यिकी तंत्रों के डेटा गेप्स को रेखांकित करने तथा उन क्षेत्रों की पहचान करने जिनमें सुदृढ एवं निरंतर अधिक डाटा संग्रहण की आवश्यकता हैं, में राज्यो/ केन्द्र शासित प्रदेशों का सहयोग करना है।
- एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण दिसम्बर, 2018 में जारी किया गया।

4. एस. डी. जी इण्डिया इण्डेक्स के प्रथम तथा द्वितीय संस्करण क्रमश: जारी किऐ गए–

(A) दिसम्बर 2018 और दिसम्बर 2021

(B) दिसम्बर 2019 और दिसम्बर 2020

(C) दिसम्बर 2019 और दिसम्बर 2021

(D) दिसम्बर 2018 और दिसम्बर 2019

उत्तर—(D)

व्याख्या—एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण दिसम्बर, 2018 में जारी किया गया, जिसमें 13 सतत् विकास गोल्स् के 62 संकेतको का उपयोग किया गया है, इसके बाद इंडेक्स का द्वितीय वर्जन दिसम्बर, 2019 में जारी किया गया।

12 बजट : 2023-24 [Budget : 2023-24]

1. राजस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 3,90,856 करोड़ रू का बजट प्रस्तुत किया है।
2. इसमें 24,895.67 करोड़ रू का राजस्व घाटा (Revenue Deficit) है।
3. इसमें 61,771.92 करोड़ रू का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य हैं ?

(A) 1 और 3 (B) 1 और 2
(C) 2 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(B)

व्याख्या—मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3,90,856 करोड़ रू का बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया है, जिसमें 24,895.67 करोड़ रू राजस्व घाटा (Revenue Deficit) तथा 62,771.92 करोड़ का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) होने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

राजस्व घाटा—किसी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी आय और व्यय के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है।

राजकोषीय घाटा—किसी वित्तीय वर्ष के राजस्व घाटे और सरकार द्वारा लिये गए ऋण पर ब्याज तथा अन्य देयताओं के भुगतान को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।

2. राजस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. शेरगढ़ - बारां, समदड़ी-बाड़मेर, बज्जू (कोलायत) बीकानेर, छारेडा-दौसा, आमेर-जयपुर, झालामण्ड (लूणी), जैसला (घंटियाली)-जोधपुर एवं जैतारण-पाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।
2. विशाला-बाड़मेर, भुसावर-भरतपुर, तालचिडी-दौसा, में राजकीय महाविद्यालय खोलना प्रस्तावित हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/सें कथन सत्य है?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) न तो 1 और न ही 2 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(B)

व्याख्या—

- शाहबाद (किशनगंज)-बारां, समदड़ी-बाड़मेर, बज्जू (कोलायत) बीकानेर, छारेडा-दौसा, आमेर-जयपुर, झालामण्ड (लूणी), जैसला (घंटियाली)-जोधपुर एवं बर-पाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।
- राजकीय महाविद्यालय -विशाला-बाड़मेर, भुसावर-भरतपुर, तालचिड़ी-दौसा, फलसुण्ड -जैसलमेर, बिसाऊ (मंडावा)-झुंझुनूं, कुचामनसिटी, खजवाना, रियाबड़ी -नागौर एवं सूरौठ (हिण्डौन सिटी)-करौली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

3. राजस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिलें में जनजातीय आवासीय विद्यालय खोला जायेगा?

(A) जालौर (B) दौसा
(C) बांसवाड़ा (D) कोटा

उत्तर—(A)

व्याख्या—राजस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 के अनुसार - बेड़ा, बाली (पाली), सिरोही, जालौर व जैसलमेर में जनजाति आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राजस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 के अनुसार चौमू-जयपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खोला जायेगा तथा मानसरोवर -(जयपुर) स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की क्षमता 100 से बढ़ाकर 500 की जायेगी।
2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापोल (जयपुर) में उर्दू विषय शुरू किया जायेगा।
3. राजकीय कन्या महाविद्यालय ब्यावर-अजमेर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहनलाल शर्मा के नाम पर किया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त में से कौन सा/सें कथन सत्य है?

(A) 1 और 3 (B) 1 और 2
(C) 2 और 3 (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर—(C)

व्याख्या—

- राजस्थान के वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 के अनुसार दूदू (जयपुर) में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास खोला जायेगा तथा मानसरोवर (जयपुर) स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 की जायेगी।
- राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापोल (जयपुर) में उर्दू विषय शुरू किया जायेगा।

13 विभिन्न नीतियाँ एवं रिपोर्ट [Various Policies and Reports]

पशुधन वार्षिक प्रतिवेदन-2022-2023, (भारत सरकार) एवं नवीनतम पशुधन रिपोर्ट (राजस्थान) - 2019

1. पशुधन वार्षिक रिपोर्ट-2022-23 (भारत सरकार) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(1) यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ) द्वारा जारी की जाती हैं।

(2) भारत में पशुधन और कुक्कुट पालन के व्यापक संसाधन हैं, जो ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(3) 20वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन बोवाईन, 52.13 मिलियन भेड़ें तथा 184.31 मिलियन बकरियाँ हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य हैं ?

(A) केवल 1 और 2 (B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3 (D) उपर्युक्त सभी।

उत्तर—(C)

व्याख्या—पशुधन वार्षिक रिपोर्ट ''पशुपालन और डेयरी विभाग मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (भारत सरकार)'' द्वारा जारी की जाती है।

- 20 वीं पशुगणना के अनुसार देश में लगभग 303.76 मिलियन बोवाईन, 76.26 मिलियन भेड़ें, 148.88 मिलियन बकरियाँ और लगभग 9.6 मिलियन सुअर हैं।

2. कथन (A)- राजस्थान में पशुपालन केवल कृषि की सहायक क्रिया ही नही, अपितु यह एक बड़ी आर्थिक क्रिया भी है।
कारण (R)- राजस्थान की शहरी तथा ग्रामीण दोनों अर्थव्यवस्थाओं में कृषि व पशुपालन एक ही धुरी के दो पहियों की भांति माने गये है।
कूट:

1. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या हैं।
2. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं हैं।
3. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत हैं।
4. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही हैं।

उत्तर—(C)

व्याख्या—राजस्थान में पशुपालन केवल कृषि की सहायक क्रिया ही नहीं है, अपितु एक बड़ी आर्थिक क्रिया भी है, विशेष रूप से सूखे व अर्द्ध-सूखे क्षेत्रों में, इस प्रकार यह बार-बार उत्पन्न होने वाली अभाव की दशाओं में अत्यधिक जरूरी बीमा स्थिति उपलब्ध कराती है।

- फसलों के उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन राजस्थान में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है।
- राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि व पशुपालन एक ही धुरी के दो पहियों की भाँति माने गये हैं।

3. निम्नलिखित कथनो पर विचार कीजिए -

(1) राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन (Milk Production) का अंश लगभग 14% हैं।

(2) बकरी के मांस के उत्पादन में राजस्थान का भारत में अंश 25% हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य हैं ?

(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) न तो 1 और न ही 2 (D) उपर्युक्त सभी।

उत्तर—(C)

व्याख्या—राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन (Milk Production) का अंश लगभग 9% तथा बकरी के मांस का अंश 30% हैं।

- राजस्थान में दूध व दूध से बने अन्य पदार्थ, ऊन, मांस, चमड़ा आदि उद्योगों का आधार पशुधन है।

4. वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितने लाख आँकी गई थी ?

(A) 568.0 लाख (B) 569.3 लाख
(C) 55.70 लाख (D) 566.0 लाख

उत्तर—(A)

व्याख्या—वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या 568.0 लाख आँकी गई है, जो 2012 से कुछ कम है। यह वर्ष 2012 में लगभग 577 लाख आँकी गई थी। वर्तमान में राज्य में देश का 10.60 % पशुधन हैं।

5. कथन (A)-पशुधन उत्पाद तथा कृषि आपस में जुड़े हुए हैं तथा दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और समग्र खाद्य सुरक्षा के लिए दोनों महत्त्वपूर्ण हैं।
कारण (R) - पशुधन क्षेत्र केवल भारतीय अर्थव्यवस्था का उप-क्षेत्र है न की कृषि क्षेत्र का उप क्षेत्र हैं।
कूट :

(A) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, तथा कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण हैं।
(B) कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), कथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।
(C) कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
(D) कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सहीं है।

DIVINE
CIVIL SERVICES ACADEMY

IAS • RAS

Rank Improvement Program *for* RAS MAINS

उन सभी के लिए जो रैंक सुधार करना चाहते है तथा उनके लिए भी जो प्रथम प्रयास में ही अच्छी रैंक प्राप्त करना चाहते है।

- अधीनस्थ सेवा अधिकारियों की मांग पर आधारित
- विख्यात विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन
- उत्तर लेखन पर विशेष बल
- गुणवत्ता सुधार हेतु विशेष प्रयास
- प्रत्येक विषय में अंक बढ़ाने हेतु विशेष रणनीति
- छोटा बैच साईज एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन

Offline/Online Batches

Download our app for online classes
Divine Civil Services Academy

Main Triveni Chauraha,
Gopalpura Bypass, Jaipur-302018

900-900-3843

राजस्थान प्रैक्टिस सीरीज़ की 4 पुस्तकें

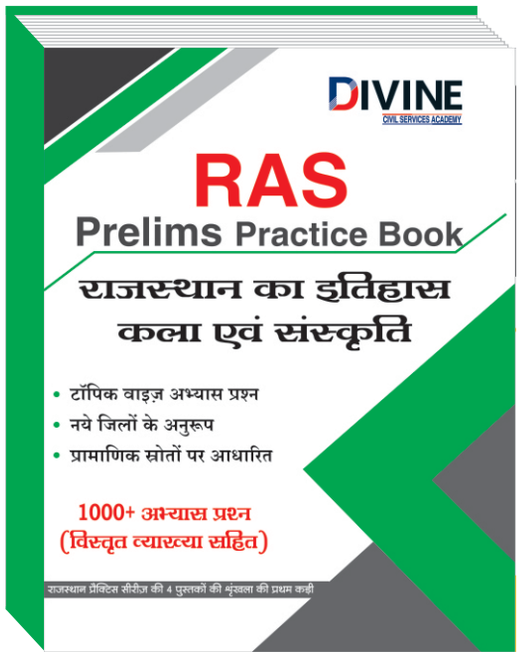

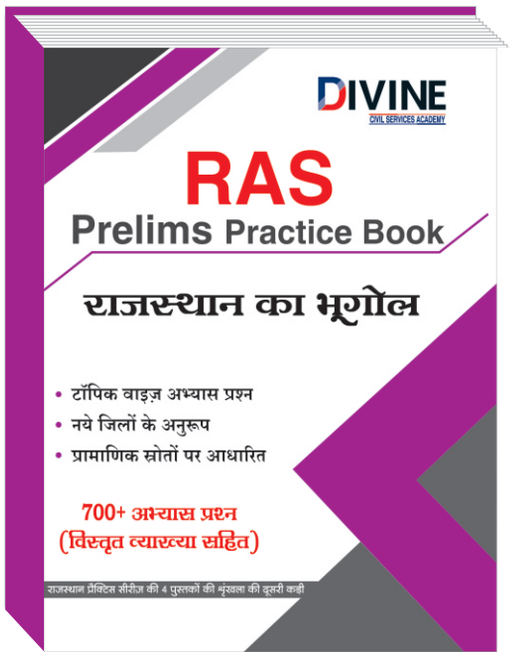

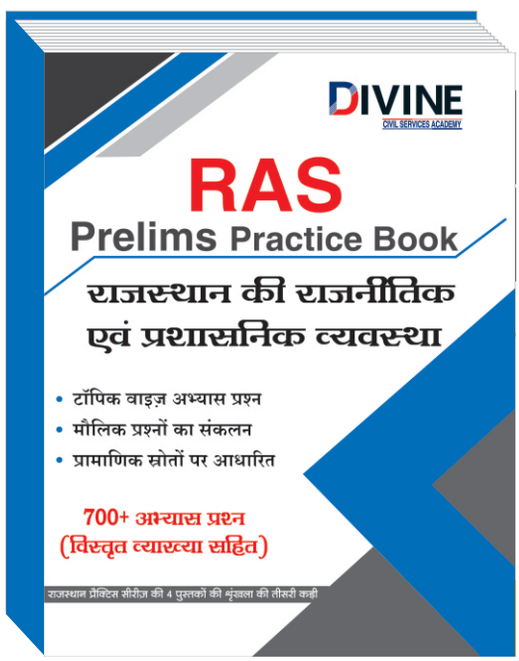

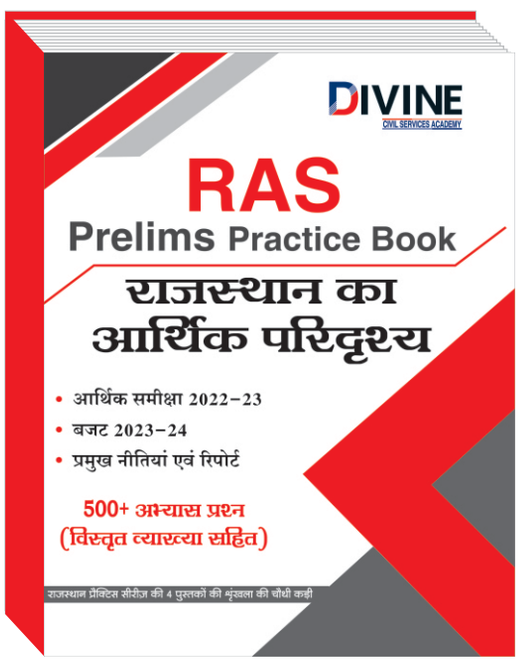

Divine Civil Services Academy
Main Triveni Chauraha, Gopalpura Bypass,
Jaipur-302018 ✆ **900-900-3843**

www.divinecivilacademy.com • email: divinecivilacademy@gmail.com

Fixed Price
₹ 100/-

For Trade Orders : College Book Centre, Jaipur ✆ **90010-72000**